सुरभि सलोनी

प्रजा फाउंडेशन ने जारी किया 'मुंबई नगर-निगम पार्षद रिपोर्ट कार्ड 2021

- **पार्षदों की उपस्थिति में आई कमी, शीर्ष तीन स्थान पाने वालों में पहले नंबर पर कांग्रेस के रवि राजा दूसरे पर शिवसेना के सदानंद सरवणकर एवं भाजपा के हरीश छेड़ा को तीसरा स्थान**

मुंबई। प्रजा फाउंडेशन ने गुरुवार, 19 अगस्त, 2021 को 'मुंबई नगर-निगम पार्षद रिपोर्ट कार्ड 2021' जारी किया, जो वित्तीय वर्ष 2017-21 की अवधि में पार्षदों के प्रदर्शन की एक समेकित रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों (ERs) के प्रदर्शन को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है, ताकि नागरिकों के प्रति पार्षदों की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके तथा उन्हें संवैधानिक रूप से अनिवार्य कर्तव्यों का पालन करने में मदद मिले।
रिपोर्ट कार्ड के अनुसार, कुल पार्षदों में से केवल 10% (22) को 'ए' और 'बी' ग्रेड प्राप्त हुए हैं । शेष पार्षदों को वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 के दौरान 'समग्र प्रदर्शन' को ध्यान में रखते हुए 'सी', 'डी', 'ई' और 'एफ़' ग्रेड प्राप्त हुए हैं । वर्ष 2021 के रिपोर्ट कार्ड में शीर्ष तीन स्थान प्राप्त करने वाले पार्षदों में श्री रवि कोंडू राजा - कांग्रेस (रैंक 1 – स्कोर 81.12%), श्री समाधान सदानंद सरवणकर - शिवसेना (रैंक 2 – स्कोर 80.42%), तथा श्री हरीश रावजी छेड़ा - बीजेपी (रैंक 3 – स्कोर 77.81%) शामिल हैं। यह पाया गया है कि कार्यकाल की प्रगति के साथ-साथ पार्षदों की उपस्थिति में कमी आई है। पिछले कार्यकाल के वर्ष 2012-13 के दौरान पार्षदों की उपस्थिति 81% थी जो वर्ष 2014-

15 में घटकर 69% हो गई। इसी प्रकार, मौजूदा कार्यकाल में भी पार्षदों की उपस्थिति वर्ष 2017-18 में 82% की तुलना में वर्ष 2019-20 में घटकर 74% हो गई।

इस अवसर पर श्री निताई मेहता, संस्थापक एवं मैनेजिंग ट्रस्टी, प्रजा फाउंडेशन, ने कहा, "प्रजा इस तथ्य को स्वीकार करता है कि, कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों ने समग्र रूप से MCGM के काम-काज को प्रभावित किया, और इसी वजह से पार्षदों को विभिन्न बैठकों में भाग लेने और नागरिकों से जुड़ी समस्याओं को उठाने के कम अवसर मिले। इसलिए, इस साल प्रजा ने हर दूसरे वर्ष प्रकाशित होने वाले वार्षिक रिपोर्ट कार्ड के स्थान पर एक 'समेकित रिपोर्ट कार्ड' के प्रकाशन का निर्णय लिया है। इस समेकित रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 तक पार्षदों के प्रदर्शन से संबंधित आवश्यक आंकड़े शामिल हैं।"

प्रजा फाउंडेशन के निर्देशक, श्री मिलिंद म्हस्के ने कहा, "हाल ही में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (MCGM) द्वारा सभी 24 वार्डों में 'कोविड वॉर रूम' बनाकर कोविड के वार्ड स्तर पर प्रबंधन का विकेंद्रीकरण किया गया। यह दर्शाता है कि नागरिकों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर असरदार तरीके से एवं कुशलतापूर्वक निवारण किया जा सकता है, और इस कार्य में पार्षदों की भूमिका बेहद अहम होती है। वर्ष 2020 में लॉकडाउन के शुरुआती महीनों के दौरान, कोविड-19 महामारी के बड़े पैमाने पर प्रसार का सामना करने के लिए पार्षदों ने जमीनी स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाई। MCGM के साथ-साथ कई अन्य संगठन भी जरूरतमंद लोगों को तत्काल राहत सहायता उपलब्ध कराने के लिए एकजुट होकर काम कर रहे थे। हालांकि, इस पूरी व्यवस्था के लिए समन्वित और संवहनीय तरीके से प्रतिक्रिया देना आवश्यक है। ऐसा तभी संभव है जब विचार-विमर्श करने वाली शाखा की बैठकों का नियमित रूप से आयोजन हो, तथा हमारी सरकार को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने में सक्षम हो।"

लॉकडाउन के शुरुआती महीनों में विचार-विमर्श पूरी तरह थम गया था और कुछ महीने बाद टेक्नोलॉजी की मदद से इसे शुरू किया गया था - जो वाकई सराहनीय है। हालांकि, महामारी हो अथवा नहीं, गुणवत्तायुक्त एवं प्रभावी विचार-विमर्श के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाना चाहिए और दूरसंचार सॉफ्टवेयर का लाभ उठाकर बैठकों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया

जाना चाहिए। अप्रैल 2017 से मार्च 2020 तक, हर महीने औसतन वार्ड समिति की 24 बैठकें आयोजित की गईं। दूसरी ओर, अक्टूबर-दिसंबर, 2020 में जब वार्ड समितियों की ऑनलाइन बैठकों का आयोजन आरंभ हुआ, तो प्रति माह बैठकों की औसत संख्या बढ़कर 28 तक पहुंच गई। अगर हम अप्रैल 2017 से मार्च 2021 तक प्रति माह औसत बैठकों की संख्या पर नजर डालें - तो वार्ड समितियों की 21 बैठकों का आयोजन हुआ, वैधानिक समितियों की 32 बैठकों का आयोजन हुआ, तथा आम सभा की बैठकें महीने में 7 बार आयोजित की गईं। हालांकि, बेहतर परिचर्चा और समावेशी निर्णय लेने के लिए तकनीकी प्लेटफार्मों का लाभ उठाकर बैठकों की संख्या में काफी सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा, वर्तमान में मुंबई में 24 वार्ड हैं और वार्ड समितियों की संख्या सिर्फ 17 है। वार्ड समितियों की संख्या को बढ़ाकर वार्डों की कुल संख्या के बराबर लाने से हर वार्ड में विचार-विमर्श को प्रभावी बनाया जा सकता है, जिससे ज्यादा-से-ज्यादा संख्या में मुद्दों को उठाया जा सकता है तथा मतदाताओं की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जा सकता है। इसके अलावा, प्रभावी विचार-विमर्श और समस्या के समाधान के लिए प्रशासन को भी पार्षदों के साथ तालमेल बिठाकर काम करने की जरूरत है।

श्री म्हस्के ने कहा, "समेकित आंकड़ों पर एक नज़र डाली जाए और इसका विश्लेषण किया जाए, तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट कार्ड में पार्षदों का कुल औसत अंक 55.10% है, जबकि पिछले कार्यकाल (अप्रैल 2012 से मार्च 2016) का औसत अंक 58.92% था। अप्रैल 2017 से मार्च 2021 के दौरान, 220 में से 71 पार्षदों को 'ई' और 'एफ़' ग्रेड प्राप्त हुए हैं, जबकि सिर्फ 2 पार्षदों को 'ए' ग्रेड तथा 20 पार्षदों को 'बी' ग्रेड प्राप्त हुए हैं । 127 पार्षदों में से अधिकांश को 'सी' और 'डी' ग्रेड मिले हैं। समितियों के कुशलतापूर्वक संचालन के साथ-साथ नागरिकों की समस्याओं को सुव्यवस्थित और कारगर तरीके से हल करने में सक्षम होने के लिए पार्षदों को और बेहतर प्रदर्शन करना होगा, ताकि 'ई' और 'एफ़' ग्रेड के प्रदर्शन को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके और उन्हें प्रदर्शन के आधार पर 'ए', 'बी', 'सी' और 'डी' ग्रेड में शामिल किया जा सके।"

रिपोर्ट का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए श्री मेहता ने कहा, "टेक्नोलॉजी की मदद से विचार-विमर्श समिति की बैठकें जितनी ज्यादा होंगी, भागीदारों के बीच तालमेल भी उतना ही अधिक होगा, और शक्तियों के विकेंद्रीकरण से इस परिवर्तन को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। फिलहाल MCGM के चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा हमें यह समझना होगा कि हमारे वर्तमान निर्वाचित प्रतिनिधियों ने पिछले कार्यकाल में कैसा प्रदर्शन किया है, साथ ही यह पार्षदों के लिए भी अपने प्रदर्शन पर आत्मनिरीक्षण करने के लिए उपयुक्त अवसर साबित हो सकता है।"

Link:- [प्रजा फाउंडेशन ने जारी किया 'मुंबई नगर-निगम पार्षद रिपोर्ट कार्ड 2021 | सुरभि सलोनी (surabhisaloni.co.in)]